



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 23 दिसम्बर, 2002/2 पौष, 1924

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 16 दिसम्बर, 2002

हिमाचल प्रदेश विधान सभा विधायक सदनों में (विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवास) आबंटन करने सम्बन्धी नियम-2002

संख्या वि० स०-3 (आवास आबंटन)-37/2002.—अध्यक्ष, हि० प्र० विधान सभा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास आबंटन सम्बन्धी नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ की तिथि :

1. ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदनों में (विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास) आबंटन नियम-2002 कहलाएंगे ।
2. ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तिथि से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

1. “अध्यक्ष” हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष से अभिप्रेत है ।

2. "सचिव" हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय के सचिव से अभिप्रेत है ।

3. "आवास" से आबंटन के प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय के नियन्त्रणाधीन ऐसे मकान अभिप्रेत हैं जोकि सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु उद्दृष्ट हों ।

4. "आबंटन" से इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार निवास स्थान के अधिभोग की अनुमति प्रदान करना अभिप्रेत है ।

5. "सम्पदा अधिकारी" हिमाचल प्रदेश सरकार (सम्पदा निदेशालय) के सम्पदा अधिकारी से अभिप्रेत है ।

6. "अनुज्ञप्ति शुल्क" से विधान सभा सचिवालय द्वारा आबंटित किए जाने वाले आवासों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मासिक देय राशि अभिप्रेत है ।

3. आवास का आबंटन :

विधान सभा सचिवालय के नियन्त्रणाधीन उद्दृष्ट आवासों को सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके निवेदन की तिथि के क्रम तथा वरीयता के आधार पर आवास आबंटन सचिव विधान सभा द्वारा किया जाएगा जबकि विशेष परिस्थितियों में वरीयता के क्रम की शर्त को छोड़ कर तथा बिना बारी के आवास आबंटन अध्यक्ष विधान सभा की अनुमति से किया जाएगा :

परन्तु यदि अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अधिभोग वाले आवास को जनहित में खाली करवाना आवश्यक हो तो सचिव ऐसे आवास के आबंटन को रद्द कर सकता है तथा उसकी जगह उसी वर्ग का वैकल्पिक आवास आबंटित कर सकता है ।

4. आवास का अनुज्ञप्ति शुल्क :

इन आवासों का अनुज्ञप्ति शुल्क, वसूल करने हेतु किराया मांग पत्र सम्पदा अधिकारी हिमाचल प्रदेश द्वारा विधान सभा सचिवालय को जारी करेगा ।

5. आवास आबंटन के लिए पात्रता :

1. विधान सभा सचिवालय के नियन्त्रणाधीन उद्दृष्ट आवासों को केवल हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को ही आबंटित किए जाएंगे :

परन्तु लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों जिनकी विधायक सदन की देख-रेख हेतु तैनाती की गई हो, को भी आवास अस्थाई रूप से आबंटित किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण.—लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जिन्हें विधायक सदन की देख-रेख हेतु तैनाती के कारण आवास आबंटित किए गए हों, को अन्यत्र स्थानान्तरण पर विधायक सदन के आबंटित आवास को पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर खाली करना पड़ेगा ।

2. विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास इस शर्त पर आबंटित किया जाएगा कि पूर्व में उसे या उसके पति/पत्नी को विधान सभा सचिवालय या सरकार द्वारा आवास शिमला में आबंटित नहीं किया गया हो ।

3. बिना बारी से तदर्थ आबंटन.—कर्मचारी को बिना बारी से निम्नलिखित आधार पर तदर्थ आबंटन किया जा सकता है :—

- (i) पूर्ण दृष्टिहीन ।
- (ii) शारीरिक रूप से विकलांग (स्वन्त रूप से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया हो) ।
- (iii) सेवा की आकस्मिकतायें (exigencies of services).

6. आबंटित आवास का निरस्त किया जाना :

1. यदि आबंटित आवास का कब्जा पन्द्रह दिन के अन्दर न लिया जाए, या आबंटन अस्वीकार कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में आवास आबंटन पर पुनः विचार एक वर्ष की अवधि तक नहीं किया जाएगा ।

2. यदि आबंटित आवास में स्वयं न रह कर उसे अपने किसी रिश्तेदार या किरायेदार को दिया गया हो या आबंटित आवास यदि किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो, तो आबंटित आवास को निरस्त किया जा सकता है ।

7. आबंटित अवधि और रियायती अवधि :

इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम, 1994 के नियम-10 के अन्तर्गत विद्यमान प्रावधान (संशोधन सहित) लागू होगा ।

परन्तु यदि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय का अधिकारी या कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाता तो वे आबंटित आवास को एक वर्ष की अवधि के लिए उसी किराए पर रख सकेगा जिसकी अतिरिक्त अवधि दौगुने किराये पर विशेष परिस्थितियों में बढ़ाने का अधिकार अध्यक्ष को होगा ।

7. सेवा निवृत्ति पर अर्जित अवकाश के बदले देय वेतन का भुगतान :

सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के अर्जित अवकाश के बदले देय वेतन का भुगतान तब तक ही किया जाएगा जब तक कि उनके द्वारा आबंटित आवास को खाली नहीं किया जाता । अर्जित अवकाश के बदले देय राशि को सचिव द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति उपरान्त निकाल करके उसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ0 डी0 आर0 के रूप में रखी जाएगी जो कि सचिव के पास रोहर बतौर क्षत अधिभोग हजर्नि के प्रति अमानत रहेगी । ऐसी एफ0 डी0 आर0 सम्पदा अधिकारी से बाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही देय होगी ।

9. अन्य नियमों का लागू होना :

उपरोक्त 1 से 8 नियमों के अन्तर्गत आवास आबंटन से सम्बन्धित अपेक्षित प्रावधान न होने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य मूल) नियम, 1994 या समग्र-समय पर संशोधित नियमों में विद्यमान प्रावधान को अध्यक्ष, विधान सभा के अनुमोदन पर लागू किया जा सकेगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

सचिव,

हिमाचल प्रदेश, विधान सभा ।

